

इकाई 3 संस्थागत दृष्टिकोण

इकाई की रूपरेखा

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 संस्थागत दृष्टिकोण: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
 - 3.2.1 संस्थागत दृष्टिकोण और तुलनात्मक सरकार का उदय: ब्राइस, लॉवेल और औस्ट्रोमोस्की का योगदान
- 3.3 संस्थागत दृष्टिकोण : आलोचनात्मक मूल्यांकन
- 3.4 समकालीन तुलनात्मक अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण
- 3.5 सारांश
- 3.6 शब्दावली
- 3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें और लेख
- 3.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई में, क) संस्थागत दृष्टिकोण के प्रमुख घटकों, ख) तुलना करने में इस दृष्टिकोण के महत्व, ग) तुलना की इकाइयों, घ) इस दृष्टिकोण द्वारा विशिष्ट प्रश्नों के दिए जाने वाले उत्तर या वैकल्पिक रूप में, इस दृष्टिकोण द्वारा किन प्रश्नों का संभवतः उत्तर दिया जा सकता है और इसकी आकांक्षाएं और क्षमताएं क्या हैं? ड.) किस प्रकार यह दृष्टिकोण समानताओं और असमानताओं की व्याख्या करता है, की चर्चा की जाएगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित पक्षों की जानकारी हासिल कर सकेंगे :

- इस दृष्टिकोण में तुलना के आधार क्या हैं ?
- इसमें तुलना के उपकरण कहां से प्राप्त किए जाते हैं ?
- इस प्रकार की तुलना से कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है ?
- दूसरे शब्दों में इस दृष्टिकोण के लाभ क्या हैं ?
- इसकी सीमाएं क्या हैं ?
- आज इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है और तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में जब इस दृष्टिकोण को पहली बार अपनाया गया था तब इसका क्या महत्व था?

इस इकाई के विभिन्न भागों में उपर्युक्त वर्णित पक्षों पर विचार किया गया है। प्रत्येक भाग के अन्त में बोध प्रश्न दिए गए हैं। इकाई के अन्त में पुस्तकों और लेखों की सूची दी गई है जिसे पढ़कर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इकाई के अन्त में बोध प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको संस्थागत दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी। शब्दावली के अन्तर्गत तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में प्रयुक्त विशिष्ट अर्थों का उल्लेख किया गया है।

3.1 प्रस्तावना

तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण के संस्थागत दृष्टिकोण द्वारा संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस अध्ययन की प्रकृति (तुलनात्मक) और विषयवस्तु (संस्थाएं) बिलकुल स्पष्ट है। उदाहरण के लिए यदि किसी को संसदीय प्रजातंत्रों में ऊपरी सदन के सापेक्षिक महत्व का अध्ययन करना है तो वह विभिन्न संसदीय प्रजातंत्रों में ऊपरी सदन का अध्ययन करेगा (जैसे भारत में राज्य सभा और यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ लार्ड) और प्रत्येक मामले में उनके सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन करेगा। उसके बाद इन संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर संसदीय प्रजातंत्र में उनकी उपयोगिता और प्रासंगिकता से संबंधित सामान्यकृत निष्कर्ष और व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। जैसे - संसद के ऊपरी सदन के संघटन में प्रतिनिधिकता का अभाव है या ऊपरी सदन की वंशानुक्रम प्रवृत्ति विधायिका की प्रजातांत्रिक प्रकृति पर आघात करती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी संसद के ऊपरी सदन का अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप यह देखने के लिए कि यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ लार्ड में वंशानुक्रम क्यों चलता आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम में संसद के दोनों सदनों के विकास के विभिन्न संदर्भों (सामाजिक और आर्थिक) का परीक्षण किया जा सकता है। इसी संदर्भ में इसके अनुवांशिक स्वरूप को समाप्त किए जाने वाले मौजूदा प्रयासों को भी समझा जा सकता है।

लम्बे समय तक तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण का संबंध मुख्य रूप से संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से रहा है। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण की शुरुआत संस्थाओं के अध्ययन के साथ ही हुई थी। इसलिए यदि किसी को अध्ययन की एक शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विकास दर्शाना हो और यह देखना हो कि तुलनात्मक विधि की शुरुआत कहां से हुई थी तो उसके लिए उसे संस्थाओं का अध्ययन करना होगा। संस्थाओं के अध्ययन के दौरान न केवल तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत हुई बल्कि 1950 के दशक तक यह कमोबेश तुलनात्मक राजनीति में एक प्रमुख दृष्टिकोण बना रहा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि परम्परागत रूप से तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था। इसमें इन संस्थाओं द्वारा शक्ति के बंटवारे के विभिन्न तरीकों और विभिन्न स्तरों के बीच के संबंध और सरकार के अंगों का भी अध्ययन किया जाता है।

प्लेटो के आदर्श राज्य गणतंत्र की दार्शनिक खोज के साथ संभवतः संस्थाओं के इतिहास की शुरुआत होती है। अगले भाग में हम संस्थागत दृष्टिकोण के ऐतिहासिक विकास पर दृष्टि डालने जा रहे हैं। चूंकि यहां हम तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण के संदर्भ में मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण का अध्ययन करने जा रहे हैं इसलिए हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे कि किस समय और कैसे संस्थागत दृष्टिकोण का स्वरूप तुलनात्मक हो गया। इस पर विचार करने से पहले हम संस्थागत दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करेंगे और अन्य दृष्टिकोणों जैसे राजनैतिक व्यवस्था दृष्टिकोण, राजनैतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण आदि से इसका अन्तर स्पष्ट करेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी दृष्टिकोण का किसी समस्या के जांच पड़ताल का संबंध उसकी : क) विषय-वस्तु (क्या अध्ययन करना है), ख) शब्दावली (उपकरण या भाषा), और ग) राजनैतिक दृष्टिकोणों के चुनाव (इसी से पता चलता है कि जांच पड़ताल का दिशा पर उद्देश्य क्या है) से निर्धारित होता है। यदि इन तीन बिंदुओं के आधार पर संस्थागत दृष्टिकोण की विशेषताओं पर विचार किया जाए तो निम्नलिखित बातें सामने आएंगी। क) सरकार की संस्थाओं के अध्ययन के प्रति इसका सरोकार और सत्ता के वितरण की प्रकृति जैसे, संविधान, सरकार की कानूनी-औपचारिक संस्थाएं, ख) इसकी कानूनी और उलझी तथा अस्पष्ट शब्दावली तथा 'आदर्श राज्य' और 'अच्छी व्यवस्था' जैसे अमूर्त शब्दों और शर्तों का ऐतिहासिक प्रयोग, ग) दार्शनिक, ऐतिहासिक या कानूनी दृष्टिकोण।

जातीय केंद्रियता इस दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता है। तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत दृष्टिकोण के अन्तर्गत प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों और संस्थाओं का अध्ययन किया गया। इस प्रकार इस दृष्टिकोण के द्वारा पश्चिमी उदारवादी जनतांत्रिक संस्थाओं में इसकी अप्रत्यक्ष आस्था व्यक्त होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पश्चिमी उदारवादी प्रजातंत्र सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप है। सरकार के इस स्वरूप को 'सार्वभौम', 'मानक' माना जाता है। पश्चिमी उदारवादी प्रजातंत्र की इस 'सार्वभौम' विशेषता के अनुसार सरकार का यह स्वरूप न केवल उत्तम है बल्कि इसे सभी जगहों पर लागू किया जा सकता है। पश्चिमी उदारवादी प्रजातंत्र की 'मानकता' इसी सोच का परिणाम है। यह सरकार चलाने का सार्वभौम तरीका है और उदारवादी प्रजातंत्र उत्तम सरकार का रूप है जिसे सभी जगह अपनाया जाना चाहिए। परंतु इस उदारवादी प्रजातंत्र ने अपने हित में कुछ अपवाद भी रखे। उपनिवेशों में शासन करते वक्त औपनिवेशिक शक्तियां उदारवादी प्रजातंत्र के सिद्धांत को भूल गईं। उपनिवेशों के लिए उन्होंने अलग सिद्धांत बनाया : क) उदारवादी प्रजातंत्र की संस्थाओं का जन्म पश्चिम में हुआ है और वहीं वे कारगर सिद्ध हो सकती हैं, ख) गैर पश्चिमी देश प्रजातांत्रिक स्वशासन के अनुकूल नहीं हैं और इसके लिए उन्हें पश्चिमी साम्राज्यवादी शासन के अन्तर्गत प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखिए।

ii) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

1) संस्थागत दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं ?

.....

.....

.....

2) इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

.....

.....

.....

3.2 संस्थागत दृष्टिकोण: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन संभवतः सबसे पहले अरस्तू ने किया था जिसने यूनान के शहर-राज्यों के संविधानों और प्रथाओं का अध्ययन किया था। तथाकथित 'बर्बर' राज्यों की राजनीति से उनका वैषम्य दिखाते हुए अरस्तू ने सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उन्हें राजतंत्र, कुलीनतंत्र, प्रजातंत्र के रूप में विभाजित किया तथा इन 'आदर्श' सरकारों और उनके 'भ्रष्ट' रूपों का अंतर स्पष्ट किया। इस दौरान तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के तौर पर तथ्यों और मूल्यों के अंतःसंबंध पर बल दिया गया। इस समय संस्थानों के अध्ययन में सरकार के 'सिद्धांत और व्यवहार' का विश्लेषण करने की कोशिश नहीं की गई। जेम्स ब्राइस ने उन्नीसवीं शताब्दी के

उत्तरार्द्ध में इसी विश्लेषण पर जोर दिया था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस समय 'आदर्श' राज्यों और सरकार के प्रकारों की खोज की ओर ज्यादा झुकाव था। दूसरे शब्दों में इस समय अटकलबाजी पर ज्यादा जोर था यानी क्या होना चाहिए जैसे प्रश्नों पर विचार किया जाता था बजाए इसके कि क्या है या जो है उसका विश्लेषण किया जाए।

सोलहवीं शताब्दी में मैकिएवेली (द प्रिंस) और अठारहवीं शताब्दी के मध्य में मॉन्टेस्युक् (द स्पीरिट ऑफ लॉ) ने मौजूदा राज्यों और व्यवस्थाओं के अनुभव आधारित विवरण और तथ्यों की प्रस्तुति पर बल दिया। हालांकि मॉन्टेस्युक् के अनुयायी मुख्यतः संवैधानिक वकील थे जो अपने पेशे के कारण ज्यादा ध्यान विषय-वस्तु पर देते थे अर्थात् उनका ध्यान सरकार के काम काज के ढंग की अपेक्षा सरकार के ढांचे पर होता था। कई मामलों में, तोक्यूविले ने सरकारों के 'सिद्धांत और व्यवहार' अध्ययन की आधारशिला रखी जो बाद में हुए तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में संस्थागत दृष्टिकोण का आधार बना। (इकाई 2: तुलनात्मक अध्ययन और तुलना की विधियां, में तोक्यूविले के अमेरिका और फ्रांसीसी प्रजातंत्रों के अध्ययन को देखें) बागेहोट (द इंग्लिश कॉन्स्टीच्यूशन, 1867) ने ब्रिटिश कैबिनेट का अध्ययन करते हुए उसकी तुलना अमेरिकी कार्यकारी से की। उसके इस अध्ययन से संस्थागत दृष्टिकोण के विकास में काफी मदद मिली। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम पच्चीस वर्षों में ब्राइस, लॉविल और ऑस्ट्रोकार्स्की ने संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन और इसके फलस्वरूप तुलनात्मक सरकारों के विकास के अध्ययन को एक विशिष्ट शाखा के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।

3.2.1 संस्थागत दृष्टिकोण और तुलनात्मक सरकार का उदय: ब्राइस, लॉविल और ऑस्ट्रोकार्स्की का योगदान

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ब्राइस, लॉविल और ऑस्ट्रोकार्स्की ने संस्थागत दृष्टिकोण की विषय वस्तु और तत्पश्चात तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप और क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन कर दिया। उनके योगदानों का मूल्यांकन करते हुए जेन ब्लाइल लिखते हैं कि ब्राइस और लॉविल वस्तुतः तुलनात्मक सरकारों के वास्तविक जन्मदाता हैं जो उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम पच्चीस वर्षों में अध्ययन की एक नई शाखा के रूप में विकसित हुई। (देखें जेन ब्लाइल, द डिसिप्लिन ऑफ पोलिटिक्स, अध्याय 7: मिडल लेवल कम्पैरिजन्स)। अमेरिकन कॉमनवेल्थ (1888) और मॉडर्न डेमोक्रेसिज (1921) ब्राइस की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसिज में ब्राइस ने जनतंत्र के सिद्धांत पर विचार करते हुए विधायिकाओं की कार्यपद्धति और उनके पतन का परीक्षण किया है। लॉविल की गवर्नमेंट्स ऐंड पार्टीज इन कांटेनेन्टल यूरोप (1896) और पब्लिक ओपिनियन ऐंड पोपुलर गवर्नमेंट (1913) भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनमें उसने फ्रांस, जर्मनी, स्विटजरलैंड आदि का अलग-अलग अध्ययन किया है। इसके अलावा इन पुस्तकों में जनमत संग्रह और इसके प्रभाव का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ऐसे ही, ऑस्ट्रोकार्स्की की पुस्तक डेमोक्रेसी ऐंड द ऑरगेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज (1902) भी अपने समय की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें राजनीतिक दलों के 'जनतांत्रिक' या कुलीनतंत्र' स्वरूप पर विचार-विमर्श किया गया है। अतः यह देखना जरूरी है कि इन रचनाओं ने होनेवाले समय में संस्थाओं के अध्ययन को किस तरह आगे बढ़ाया और परिवर्तित किया।

i) सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार: पिछले भाग में हमने बताया था कि सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन दार्शनिक, अनुमानित या ज्यादातर कानूनी-संवैधानिक रहा है अर्थात् या तो इनमें 'आदर्श राज्य' जैसे अमूर्त धारणाओं की चर्चा की गई थी या सरकारों के ढांचों और कानूनी-संवैधानिक बनावट की बात की गई। उदारवादी संवैधानिक सिद्धांत को आधार बनाकर उन्होंने औपचारिक संस्थागत संरचनाओं का अध्ययन किया जिसमें उनकी कानूनी शक्तियों और कार्यों पर बल दिया

गया। 'तुलनात्मक सरकार' या 'विदेशी संविधानों' का अध्ययन इसी प्रकार किया गया। इन रचनाओं को विभिन्न देशों में संस्थागत निर्माण के संभ्रान्तों के प्रयत्न के रूप में देखा गया। इसी कारण नए आजाद देशों में संस्थाकरण के प्रति रुझान दिखाई देता है। ब्राइस और लॉवेल का मानना है कि मौजूदा अध्ययन अधूरे और पूर्वाग्रहग्रस्त हैं। उनके अनुसार सरकारों के व्यापक अध्ययन के लिए सरकारों के कानूनी-संवैधानिक ढांचों की कार्य पद्धति पर भविष्य में विचार करना चाहिए। वे बल देकर कहते हैं कि इस प्रकार के अध्ययनों में न केवल सैद्धान्तिक आधारों या सरकारों के सन्दर्भों (अर्थात् कानूनी-संवैधानिक ढांचा और सरकारी संस्थाएं) पर बल्कि 'सरकार के काम काज के ढंग' पर भी बल दिया जाना चाहिए। वकीलों की तरह केवल उनके संविधानों की बात करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इससे संचालन और उनके कार्यान्वयन में आनेवाली समस्याओं पर बात नहीं हो पाती। दूसरी ओर, सैद्धान्तिक (संवैधानिक) ढांचे के बिना आधार बनाए केवल व्यवहार या काम काज करने के ढंग पर बात करने से वह संदर्भ ही छूट जाएगा जिसके कारण कार्यान्वयन में समस्या आती है। इसीलिए ब्राइस और लॉवेल के तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण के संस्थागत दृष्टिकोण में 'सरकार के सिद्धांत और व्यवहार' के अध्ययन पर बल दिया गया।

ii) 'तथ्यों' पर बल : इन अध्ययनों का बल सरकारों की कार्य पद्धति के 'तथ्यों' का विश्लेषण कर 'व्यवहार' की जानकारी प्राप्त करनी है। व्यवहार के अध्ययन के लिए तथ्यों को खोजना, इकट्ठा और संचित करना पड़ता है। ब्राइस को इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है कि विश्लेषण को तथ्य पर आधारित होना चाहिए। 'तथ्यविहीन विश्लेषण मात्र अटकलबाजी होती है' : 'तथ्य, तथ्य, तथ्य, जब तथ्य मिल जाएं तो हमें उनका विश्लेषण करना चाहिए।' तथ्यों को इकट्ठा करते समय एक बड़ी दिक्कत यह आती है सरकारें अपने काम काज के बारे में सही-सही बताती नहीं है और तथ्यों को छिपाती है। इसलिए तथ्यों का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि सरकार और राजनीति अक्सर तथ्य छिपाते हैं या सही स्थिति नहीं स्पष्ट करते। इन बाधाओं के बावजूद राजनैतिक जीवन, दलों, कार्यकारियों, जनमत संग्रहों, विधायिकाओं आदि के लगभग सभी पक्षों के आंकड़े इकट्ठा करने का महत्व कम नहीं होता। **हर्मन फाइनर** (थ्योरी ऐंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, 1932) और **कार्ल फ्रेडरिक** (कांस्टीच्युशनल गवर्नमेंट ऐंड डेमोक्रेसी, 1932) जैसे बाद के तुलनावादियों ने भी इसके महत्व को सही ठहराया।

iii) तकनीक : तथ्यों की खोज करने के क्रम में ब्राइस और लॉवेल ने परिमाणात्मक सूचकों का उपयोग किया। उन्होंने यह महसूस किया कि सरकारों के अध्ययन में गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रकार के प्रमाणों में संतुलन होना चाहिए। अंततः ब्राइस और लॉवेल ने महसूस किया कि ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को आधार बनाने पर निष्कर्ष के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। अतएव उन्होंने ज्यादा से ज्यादा देशों का अध्ययन किया, जिनमें उस समय संवैधानिक और संवैधानिक जैसी संस्थाएं थीं। इसलिए उन्होंने पश्चिमी मध्य और दक्षिणी यूरोप की सरकारों के अध्ययन पर बल देना शुरू किया। ऑस्ट्रो-गोस्की की रचना प्रकाशित होने के बाद तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में तुलनात्मक आधार पर विशिष्ट संस्थाओं के अध्ययन पर बल देना शुरू हुआ। 1902 में ऑस्ट्रो-गोस्की ने ब्रिटेन और अमेरिका के राजनैतिक दलों का विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया। बाद में **माइकल्स** (पोलिटिकल पार्टीज, 1915) और **एम डुवरगर** (पोलिटिकल पार्टीज, 1950) ने राजनैतिक दलों की भूमिका पर महत्वपूर्ण काम किया। 1950 के दशक में **ईस्टन** और **मैकडिस** जैसे 'व्यवस्था सैद्धान्तिकों' ने संस्थागत दृष्टिकोण की प्रमुख रूप से आलोचना की और ऐसे मॉडल के निर्माण पर बल दिया जो सामान्य हो तथा जो पूरी दुनिया पर लागू होता है। इन मॉडलों या प्रारूपों के आधार पर उन्होंने विभिन्न देशों की राजनैतिक प्रक्रियाओं को समझने और समझाने का प्रयास किया। इन आलोचनाओं और संस्थावादियों द्वारा दिए गए जवाबों का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे।

नोट : i) नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखिए।

ii) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

1) उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में संस्थागत दृष्टिकोणों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3.3 संस्थागत दृष्टिकोण: आलोचनात्मक मूल्यांकन

यह एक रोचक तथ्य है कि तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण के संस्थागत दृष्टिकोण की आलोचना अलग-अलग समयों में हुई। पहली बार आलोचना का दौर 20वीं शताब्दी के आरंभ में और फिर दूसरा दौर 1950 के दशक में आया। आलोचना के प्रत्येक दौर के बाद इस दृष्टिकोण का पुनरुत्थान नए रूप में हुआ। इस शताब्दी के अंत में जब संस्थाओं के अध्ययन में तुलना नहीं की जाती थी या सीमित तुलना की जाती थी तो इस दृष्टिकोण की यह कहकर आलोचना की गई कि क) यह अनुमानों पर आधारित है, ख) यह आदेशात्मक और मानकीय है, ग) इसमें संबंधों पर ध्यान दिए बिना नियमितताओं और अनियमितताओं पर ध्यान दिया जाता है, घ) इसमें केवल पश्चिम यूरोपीय 'प्रजातंत्रों' पर विचार किया जाता है। अतः यह जातीय केंद्रित है, ङ.) यह औपचारिक ढांचे (संवैधानिक और सरकारी) पर बल देने के कारण विवराणात्मक है, च) यह ऐतिहासिक है पर विश्लेषणात्मक नहीं है, छ) इसके प्रतिपादक इस ढांचे से इस प्रकार अभिभूत हैं कि संस्थाओं का अध्ययन करते समय वे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और विचारात्मक ढांचों के अन्तर को तुलना करते समय नजरअंदाज कर देते हैं। मसलन इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ के ऊपरी सदन की तुलना, ज) उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनके अध्ययन की प्रवृद्धि पूर्वाग्रहग्रस्त और अधूरी है और सैद्धान्तिक तौर पर यह कहा गया कि उन्होंने राजनैतिक जीवन के सार तत्व को नहीं पकड़ा है। ब्राइस और उनके समकालीनों के संस्थागत दृष्टिकोण की प्रकृति और विषय में मूलभूत परिवर्तन किया। उन्होंने सीमित दायरे में सही परंतु तुलनात्मक अध्ययन शुरू किया। उन्होंने सैद्धान्तिक संदर्भों और सरकार के व्यावहारिक पक्ष को मिलाकर देखने का प्रयत्न किया। 1950 के दशक में ब्राइस, लॉविल और ऑस्ट्रोगोस्की के संस्थागत दृष्टिकोण को पुनः डेविड ईस्टन और रॉय मैकिडिस जैसे राजनैतिक वैज्ञानिकों की आलोचना का सामना करना पड़ा। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक *द पोलिटिकल सिस्टम* (1953) में ब्राइस के दृष्टिकोण की मात्र तथ्यवाद कहकर आलोचना की। ईस्टन का आरोप था कि यह दृष्टिकोण अमेरिकी राजनीति विज्ञान से प्रभावित था जो तथ्यों पर जरूरत से ज्यादा बल देता था। उन्होंने यह माना कि ब्राइस ने सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की है परंतु व्याख्यात्मक या सैद्धान्तिक मॉडल बनाने के क्रम में उन्होंने तथ्यों का अम्बार खड़ा कर दिया है जिससे सिद्धांत कमजोर हो गए हैं। (एक अन्य इकाई में आप 'व्यवस्था निर्माण' का अध्ययन करेंगे। इसमें राज्य परिघटना का अध्ययन करने में ईस्टन के 'व्यवस्था दृष्टिकोण' को आधार बनाया गया है। अतएव यह समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ईस्टन क्यों यह महसूस करते थे कि ब्राइस के दृष्टिकोण ने अमेरिकी राजनीति विज्ञान को गुमराह कर गलत रास्ते पर डाल दिया है।) जीन ब्लाइल ने ईस्टन की आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि इस सिद्धांत में तथ्यों का अम्बार लगाया गया है यह आलोचना सही नहीं है। वस्तुतः समग्र राज्य विश्लेषण के लिए राजनीति वैज्ञानिकों के पास बहुत कम तथ्य मौजूद थे। वास्तविकता में अधिकांश देशों खासकर

साम्यवादी देशों और तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों की प्रमुख संस्थाओं की संरचना और गतिविधियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। अतः ज्यादा तथ्य इकट्ठा करने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह इस तथ्य को देखते हुए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकारें तथ्य उपलब्ध नहीं करातीं और छिपाने की कोशिश करती हैं। अधिक वैश्विक या व्यवस्थित दृष्टिकोण के समर्थकों द्वारा संस्थाओं और कानूनी व्यवस्थाओं संबंधी तथ्यों की उपयोगिता के अवमूल्यन को ब्लांडेल ने पूरी तरह गलत बताया। राजनैतिक परिघटना का अध्ययन उसके संस्थागत और कानूनी ढांचे में किया जा सकता है। राजनैतिक जीवन का पूर्ण अध्ययन करने के लिए इन सभी पक्षों का अध्ययन और तुलना करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में प्रभावी विश्लेषण करने के लिए तथ्यों की जरूरत पड़ती है। तथ्यों या आंकड़ों के अभाव में तर्क दिया ही नहीं जा सकता है। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि राजनीतिक विश्लेषण के अध्ययन में जिन तथ्यों की जरूरत होती है उन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। 1955 में रॉय मैक्रिडिस ने सरकार के तुलनात्मक अध्ययन को नई दिशा प्रदान करने की आवश्यकता की ओर इशारा किया था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मौजूदा तुलनात्मक अध्ययन नाममात्र का तुलनात्मक है। मैक्रिडिस के अनुसार संस्थागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धति गैर तुलनात्मक, सीमित, स्थिर और विवरणात्मक है। उनके अनुसार अधिकांश संस्थागत दृष्टिकोण के अध्ययन में विवरण भरे पड़े हैं। इसमें किया गया विश्लेषण ऐतिहासिक या वैधानिक है और इसलिए संकुचित भी है (देखिए रॉय मैक्रिडिस, *द स्टडी ऑफ कम्परेटिव गवर्नमेंट*, पृ. 7-12) हालांकि 1950 के दशक में और उसके बाद भी बराबर तथ्यों की कमी महसूस की जाती रही जिससे सही निष्कर्ष निकाला जा सके। ब्लांडेल के अनुसार तथ्यों के अधिकांश की अपेक्षा मॉडलों की अधिकता ज्यादा थी। ब्लांडेल ने इस बात पर बल दिया है कि तथ्यों के बिना प्रारूपों के निर्माण से गलत सूचनाएं मिलती हैं। जिन देशों के बारे में सूचनाएं प्रचारित होने की संभावना अधिक होती है और कई बार इससे उन देशों के बारे में पूर्व धारणा बन जाती है। 1971 में लैटिन अमेरिकी विधान सभाओं के बारे में लिखते हुए डब्ल्यू एच अगोर ने यह टिप्पणी की थी कि आमतौर पर यह माना जाता है कि विधान सभाएं बहुत कमजोर थीं। उनके अनुसार इस प्रकार के कथन पूर्णतः पूर्व धारणाओं पर आधारित थे। तथ्यों के अभाव में इन्हीं पूर्व धारणाओं के आधार पर संप्रत्यक्ष अध्ययन किया गया था। इसलिए संस्थागत दृष्टिकोण के अनुयायियों ने स्पष्ट रूप से तथ्यों को जुटाने और तथ्य जुटाने के तरीकों की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया। हालांकि इन आलोचनाओं के बाद इस दृष्टिकोण में तुलनात्मक प्रवृत्ति बढ़ी और गैर पश्चिमी देशों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा कानूनी-संवैधानिक ढांचों द्वारा निर्धारित न की गई संरचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास भी किया गया। उदाहरण के लिए जी सारटोरी ने अपनी पुस्तक *पार्टीज ऐंड पार्टी सिस्टम्स* (1976) के अध्ययन में सीमित रूप में सही लेकिन साम्यवादी देशों और तीसरी दुनिया के देशों को भी शामिल किया।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखिए।

ii) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

1) ईस्टन और मैक्रिडिस के अनुसार संस्थागत दृष्टिकोण की क्या सीमाएं थीं ?

.....

.....

.....

.....

2) ब्लांडेल ने संस्थागत दृष्टिकोण के पक्ष में क्या जवाब दिया?

.....

.....

.....

.....

3.4 समकालीन तुलनात्मक अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण

1950 के दशक तक तुलनात्मक राजनीति में संस्थावाद कमोबेश एक विशिष्ट दृष्टिकोण बना रहा। पिछले भाग (3.2) में हम बता चुके हैं कि ब्राइस, लॉवेल और ऑस्ट्रोप्रोस्की की रचनाओं के जरिए यह दृष्टिकोण उभर कर सामने आया। हरमन फाइजर (*थ्योरी ऐंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स*, 1932) और कार्ल फ्रेडरिक (*कांस्टीच्यूशनल गवर्नमेंट ऐंड डेमोक्रेसी*, 1932) ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। उदारवादी संवैधानिक सिद्धांत के समर्थन में इन विद्वानों ने औपचारिक संस्थागत ढांचों का अध्ययन करते हुए उनकी कानूनी शक्तियों और कार्यों पर बल दिया। तुलनात्मक सरकार या विदेशी संविधानों के अध्ययन में इन रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कई देशों में संस्थागत निर्माण के प्रयासों में इसे प्रासंगिक माना गया है। नए आजाद देशों को महत्व मिला है। इस सिद्धांत में संस्थागत निर्माण पर बल दिए जाने के कारण ऐसा हुआ है।

संस्थागत दृष्टिकोण का मुख्य बल (विषय वस्तु) इस प्रकार था, क) कानून और संविधान, ख) संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र, कानूनी और विधायी उपकरणों के विभिन्न रूपों को समझने के लिए सरकार और राज्य का ऐतिहासिक अध्ययन, ग) सरकार के विभिन्न ढांचों के कार्य करने के तरीके (सिद्धांत और व्यवहार)। इसमें सत्ता के बंटवारे का भी अध्ययन किया जाता है जिसके तहत राष्ट्र और राज्य, केंद्र और स्थानीय सरकार, प्रशासन और नौकरशाही, कानूनी और संवैधानिक प्रचलनों और सिद्धांतों के परस्पर संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के पीछे प्रजातंत्र की पश्चिमी अवधारणा निहित है। प्रस्तावना (3.1) में हमने बताया है कि प्रजातंत्र का न केवल जन्म ही पश्चिम में देखा गया है बल्कि उसे उसी रूप में सभी जगह इसे लागू किए जाने की कल्पना की गई है और सलाह दी गई है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं इससे अध्ययन पश्चिम केंद्रित हो गया है अर्थात् पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया है। ब्लांडेल का मानना है कि 1950 के दशक में इस दृष्टिकोण के प्रभाव में इस कारण से भी गिरावट आई क्योंकि इसमें गैर पश्चिमी (उदारवादी) सरकारों खासकर पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों और एशिया तथा लैटिन अमेरिका के नए आजाद हुए देशों को शामिल नहीं किया गया। अतः सिद्धांत और व्यवहार को साथ लेकर चलने का दावा करनेवाला यह दृष्टिकोण उदारवादी संवैधानिक प्रजातंत्रों का अध्ययन करने के लिए अपने ढांचों को बदल नहीं सका। 1950 के दशक में संस्थागत दृष्टिकोण के पतन का एक कारण यह भी था कि व्यवस्था सिद्धांतकारों ने तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बजाए प्रेरक सामान्यीकरण के आधार पर सिद्धांत विकसित किए गये।

1960 के अंत और 70 के दशक में संस्थागत दृष्टिकोण फिर से एक नए रूप में सामने आया जिसे नौसंस्थावाद कहा जाता है। जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं : क) नए संस्थावाद में संस्थाओं के सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण राज्य और इसकी संस्थागत संरचनाओं के महत्व पर बल देता है। (पी इवेन्स, डी र्यूशेमेयर और टी स्कॉकपॉल सं. *ब्रिगिंग द स्टेट बैक इन*, 1985)। इसमें उस बृहद ढांचे की चर्चा नहीं की गई जिसके तहत संस्थाएं काम करती हैं (संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण में यह पद्धति अपनाई जाती है)। इसके बजाए इसमें संस्थाओं के आपस में जुड़े रहने के तरीके पर बल दिया जाता है। ख) ढांचों से अपने को दूर रखने के बावजूद

यह दृष्टिकोण सामान्यीकृत निष्कर्षों से बच नहीं पाता। तथ्यों के संग्रह में भी कोई कमी नहीं आती। इन विभिन्न पद्धतियों में संतुलन स्थापित करने के लिए अर्थात् सामान्यीकृत निष्कर्षों के लिए तथ्य आधारित अध्ययन करने में संस्थागत दृष्टिकोण कुछ बातों की सावधानी रखता है:

i) तथ्यों की ठीक से जांच कर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और, ii) प्रेरक विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि सामान्यीकरण के दौरान भी इन तथ्यों के निकट रहा जा सके (देखिए जेन ब्लाडेल, *दिन ऐंड नाउ. कम्परेटिव पॉलिटिक्स*, पृ 160); iii) इस दृष्टिकोण का बल कमोबेश तथाकथित मध्यम दूरी के विश्लेषण पर रहा है जहां विशिष्ट संस्थाओं के तथ्यों को इकट्ठा कर बड़े क्षेत्रों पर विचार किया जाता है जिसमें तुलना की काफी गुंजाइश होती है। परंतु यहां प्रेरक प्रारूपों का उपयोग किए बिना तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार राजनैतिक दलों (उदाहरणस्वरूप जी. सारटोरी की पुस्तक *'पार्टीज ऐंड पार्टी सिस्टम्स'*, 1976, बज और एच केमन, *'पार्टीज ऐंड डेमोक्रेसी'*, 1990), दबाव समूहों, (एफ. केसल्स, *प्रेसर ग्रुप्स ऐंड पॉलिटिकल कल्चर*, 1967), न्यायपालिका, (जी सुबर्ट, *ज्यूडिसियल बीहेवियर*, 1964), विधायिकायों (एम.एल.मेजी, *कम्परेटिव लेजिसलेचर्स*, 1979; ए कॉर्नबर्ग, *लेजिसलेचर्स इन कम्परेटिव पर्सपेक्टिव*, 1973, जेन ब्लाडेल, *कम्परेटिव लेजिसलेचर्स*, 1973; डब्ल्यू.एच.आगर, *लैटिन अमेरिकन लेजिसलेचर्स*, 1971) और सेना (एस. ई. फिनर, *मैन ऑन हॉर्सबैक*, 1962) का अध्ययन किया जाता है।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखिए।

ii) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

1) सभी तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण में संस्थागत दृष्टिकोण की क्या स्थिति है ?

.....

.....

.....

.....

3.5 सारांश

संस्थागत दृष्टिकोण अपने विभिन्न रूपों में तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण का एक प्रमुख घटक रहा है। आरंभ से ही संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन राजनैतिक विश्लेषण के केंद्र में रहा है। इसी के तहत *रिपब्लिक* में प्लेटो ने आदर्श राज्य की खोज की और अपनी *'पॉलिटिक्स'* में अरस्तु ने राज्यों के प्रकार बताए। इस दृष्टिकोण का क्लासिकल और आरंभिक स्वरूप दार्शनिक और अनुमान आधारित था जिसमें आदर्श राज्यों की चर्चा की जाती थी और सरकार के काम काज की स्थिति के नुस्खे बताए जाते थे। मॉन्टेस्क्यू और उसके अनुयायियों ने इस दृष्टिकोण को प्रजातंत्र के कानूनी-संवैधानिक ढांचों से जोड़कर देखा। परंतु उदारवादी संवैधानिक प्रजातंत्र की संस्थाओं में इस आस्था के बावजूद सरकारी काम काज के तरीके का अध्ययन नहीं हो सका। अभी हाल तक, खासतौर पर उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक, राजनीति वैज्ञानिक और कानूनी विशेषज्ञ कानूनी-संवैधानिक ढांचों से मुक्त नहीं हो पाए थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण संविधानों और सरकार की कानूनी औपचारिक संस्थाओं तथा उदारवादी प्रजातंत्र के मानवीय मूल्यों से प्रभावित था। इस दृष्टिकोण को औपनिवेशिक शासकों ने अपने उपनिवेशों में यूरोपीय उदारवादी मूल्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी बढ़ावा दिया। विभिन्न देशों में सभ्रांतों द्वारा संस्था निर्माण में भी संस्थावादियों के काम काफी प्रासंगिक रहे हैं। इसीलिए नए आजाद हुए देशों में संस्थावाद के प्रति

इतना झुकाव बढ़ा। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही ब्राइस, लॉवेल और ऑस्ट्रोगोस्की जैसे विद्वानों ने संस्थाओं के अध्ययन के लिए नई दिशाओं की खोज की। क) उन्होंने सैद्धांतिक-कानूनी-संवैधानिक ढांचे का एक साथ अध्ययन किया और उनके काम काज के तरीके से जुड़े तथ्य इकट्ठे किए और, ख) अन्य देशों की संस्थाओं का अध्ययन कर उन्होंने अपने अध्ययन को तुलनात्मक दिशा प्रदान की। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी के पहले 25 वर्षों में इस सिद्धांत ने सीमित रूप से ही सही पर तुलनात्मक स्वरूप अस्तित्व कर लिया था और इसमें विश्लेषण, सिद्धांत और संस्थाओं के कामकाज करने के तरीकों को भी शामिल कर लिया था। 1950 के दशक के दौरान इस दृष्टिकोण पर ईस्टन और मैक्रिडिस जैसे 'व्यवस्था निर्माताओं' ने काम किया। उन्होंने इस दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर की— क) तथ्यों पर जरूरत से ज्यादा बल देना, ख) ऐसे सिद्धांतों का अभाव जो दूसरे देश की संस्थाओं पर भी लागू हो सके, ग) तुलनात्मक स्वरूप का अभाव। इन सिद्धांतकारों ने एक समग्र या वैश्विक मॉडल या व्यवस्था बनाने पर बल दिया जो दुनिया भर के सभी देशों की संस्थाओं के काम काज को व्याख्यायित कर सके। संस्थागत दृष्टिकोण के प्रतिपादकों की इस बात के लिए भी आलोचना की गई कि उनका अध्ययन पश्चिम केंद्रित है अर्थात् उन्होंने अपने अध्ययन के घेरे में तीसरी दुनिया के देशों और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों की संस्थाओं को शामिल नहीं किया है। इन देशों का अध्ययन न करने से यह सिद्धांत सभी देशों पर लागू नहीं होता है और इसमें केवल पश्चिमी उदारवादी संस्थागत प्रजातंत्रों का ही सैद्धान्तिक विवेचन किया जाता है। इनके पास विकासशील और साम्यवादी दुनिया के देशों की संस्थाओं को समझने का कोई तरीका नहीं था; इसलिए धीरे-धीरे इस दृष्टिकोणों का प्रभाव कम होता चला गया। परंतु 1960 के दशक के अंत और 70 के दशक के आरंभ में यह दृष्टिकोण फिर से नए रूप में उभरा। इसमें तथ्यों पर बल दिया गया। सामान्यीकृत सैद्धान्तिक वक्तव्य भी दिए गए। केवल मॉडल बनाने के प्रयत्न नहीं किए गए।

बोध प्रश्न 5

नोट : i) नीचे दिए गए स्थान में अपना उत्तर लिखिए।

ii) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान कीजिए।

- 1) संस्थागत दृष्टिकोण का ऐतिहासिक विकास प्रतिपादित कीजिए। प्रत्येक चरण की विशेषताएं बताते हुए उनका अन्तर स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

- 2) आपके विचार में संस्थागत दृष्टिकोण राजनैतिक प्रक्रिया के तुलनात्मक अध्ययन के लिए कितना प्रभावी सिद्धांत है ?

.....

.....

.....

.....

3.6 शब्दावली

| | |
|---------------------|--|
| संरूपित वर्णन | : बिना किसी स्पष्ट अवधारणात्मक ढांचे के कुछ देशों का विस्तृत वर्णन करते हुए राजनैतिक संस्थाओं का अध्ययन। |
| अनुभववाद | : दर्शन का एक क्षेत्र जिसमें ज्ञान और अनुभव को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया जाता है। शुद्ध अनुभववादी यह मानते हैं कि सही ज्ञान का आधार तथ्य हैं जो अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। |
| जातीय केंद्रियता | : अपनी संस्कृति पर आधारित मूल्यों और सिद्धांतों को दूसरे लोगों और समूहों पर लागू करना; जातीय केंद्रियता में एक पूर्वाग्रह या मिथ्यावर्णन होता है। |
| तथ्य | : तथ्य किसी मामले से सम्बद्ध होता है और इसका संबंध पर्यवेक्षण और अनुभव से होता है। |
| औपचारिक-वैधानिकता | : संवैधानिक रूझान जिसमें मंत्रिमंडलों, विधायकों, न्यायालयों और नौकरशाहियों के काम काज के तरीके से सम्बन्धित नियमों का विस्तृत उल्लेख होता है। |
| उदारवादी प्रजातंत्र | : एक प्रकार का प्रजातांत्रिक शासन जो सीमित सरकार के सिद्धांत और जनता के आदर्श के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसकी 'उदारवादी' विशेषताएं सरकार पर लगाई गई आंतरिक और बाहरी नियंत्रणों से प्रतिबिंबित होती हैं जिसका निर्माण जनता को स्वतंत्रता प्रदान करने तथा नागरिकों को राज्य से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। इसकी जनतांत्रिक प्रकृति नियमित और प्रतियोगात्मक अनुभव की प्रणाली पर आधारित होती है। जिसमें वयस्क मताधिकार और राजनैतिक समानता के आधार पर मतदान कराया जाता है। |
| मॉडल | : मॉडल या प्रारूप अनुभव सिद्ध आंकड़ों का सैद्धान्तिक प्रतिनिधित्व है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्क्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। |
| गैर तुलना | : तुलनात्मक सरकार के क्षेत्र के अधिकांश ग्रंथों में या तो किसी एक देश का अध्ययन किया गया है या कुछ देशों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कर दिया गया है। |
| मानकीय | : मूल्यों और आचरण के मानकों का नुस्खा 'क्या है' के बजाए 'क्या होना चाहिए'। |
| संकुचित दृष्टिकोण | : सीमित दायरे में बंधा होना। उदाहरण के लिए तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन किए जाने वाले देशों के चुनावों में एक खास तरह का पूर्वाग्रह दिखाई देता है और इन पर विचार करने के लिए प्रयुक्त निर्धारक तत्वों में भी एक प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण दिखाई देता है। इस प्रकार के अध्ययन में ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, और अमेरिका का अध्ययन किया जाता है। |
| नज़रिया | : किसी चीज को देखने, व्याख्या करने और सामाजिक यथार्थ का अनुभव करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में नज़रिया या दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। |

मूल्य : मूल्य एक प्रकार के वस्तुव्य होते हैं जिसमें निर्णय जुड़ा होता है और इसमें एक वस्तुनिष्ठता होती है। मूल्य एक प्रकार की कल्पना होती है। उनमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती और वे सभी लोगों पर लागू नहीं होते।

3.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें और लेख

एक्टर, डेविड. ई, 'कम्परेटिव पॉलिटिक्स, ओल्ड ऐंड न्यू' रॉबर्ट ई. गूडिन ऐंड कैस एच.डी. क्लिंगमैन में, सं., अ न्यू हैडबुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, 1996

ब्लांडेल, जेन, 'द डिस्प्लिन ऑफ पॉलिटिक्स, बटरमॉर्थस, लंदन', 1981, (अध्याय 7: मिडिल लेवल कम्पेरिजन्स)

ब्लांडेल जेन देन ऐंड नाउ: कम्परेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्टडिज, XLVII 1999, पृ. 152-160

वियारडा, हॉवर्ड, जे., 'न्यू डाइरेक्शन्स इन कम्परेटिव पॉलिटिक्स', वेस्टव्यू प्रेस, बोल्डर, 1985

3.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

- 1) यह दृष्टिकोण विभिन्न संस्थानों की परस्पर तुलना के अध्ययन पर आधारित है। इसमें सामान संस्थाओं जैसे कार्यकारी विधायिका आदि के गठन और कार्यों की समानताओं और असमानताओं की तुलना की गई है और निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है।
- 2) समान संस्थाओं की तुलना; उनके उद्भव, विकास और कार्यपद्धति का संदर्भ; निष्कर्ष प्रस्तुत करना; निष्कर्ष के आधार पर परिवर्तन या विकास के लिए सुझाव देना।

बोध प्रश्न 2

- 1) देखिए भाग 3.3
- 2) बॉन्डल ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की सीमाएं बताई हैं और यही कहा है कि इसके द्वारा संस्थाओं के बारे में पूरी सूचना नहीं मिल पाती है उसने संस्थाओं और कानूनी ढांचों के महत्व पर भी बल दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भाग 3.3।

बोध प्रश्न 3

- 1) देखिए भाग 3.4

बोध प्रश्न 4

- 1) पूरी इकाई के आधार पर अपना उत्तर लिखिए।
- 2) भाग 3.5 देखिए और पूरी इकाई के आधार पर अपना उत्तर लिखिए।